RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 27 जुलाई 2023 वर्ष 05 अंक 95 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 8 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

'सीमा शुल्क विभाग के पास सील करने का अधिकार नहीं'

हाईकोर्ट ने कंपनी के परिसर को खोलने का दिया निर्देश

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा किसी परिसर को सील करना सख्त कार्रवाई के समान है, जिसके परिणामस्वरूप किसी अचल संपत्ति को रखने, इस्तेमाल करने और कब्जा करने के 'किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़' होती है। अदालत ने यह भी कहा कि विभाग के पास ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार भी नहीं है।

न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा कि उनकी राय है कि तलाशी लेने की शक्ति का मतलब सील करने की शक्ति नहीं हो सकती है और सीमा शुल्क अधिकारियों को एक कंपनी के नवी मुंबई परिसर को खोलने का निर्देश दिया। यह आदेश नारायण पावर सॉल्यूशंस की ओर से दायर याचिका पर पारित किया गया है। पावर सॉल्यूशंस ने वकील सुजय कांतावाला के जरिए याचिका दायर की थी, जिसमें नवी मुंबई में उनके कार्यालय परिसर को खोलने की मांग की गई थी। कांतावाला ने तर्क दिया था कि सीमा शुल्क विभाग के पास सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिसर को सील करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अदालत ने कहा, 'परिसर को सील करने की शक्ति एक कठोर शक्ति है। हमारी राय में ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि कानून द्वारा इसे स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।' सीमा शुल्क अधिकारियों के पास सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105 के तहत परिसर को सील करने की स्पष्ट शक्ति नहीं होगी। अदालत ने कहा कि परिसरों को सील करना एक कठोर कार्रवाई है।

पीठ ने कहा, 'इसका परिणाम किसी भी अचल संपत्ति को रखने, उसका इस्तेमाल करने और उस पर कब्जा करने के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ के रूप में सामने आता है। संपत्ति का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या अन्यथा किया जा सकता है, इसलिए परिसर को सील करने की किसी भी कार्रवाई का संविधान के अनुच्छेद 300 ए द्वारा गारंटीकृत परिसर का उपयोग करने और कब्जा करने के लिए व्यक्ति के कानूनी अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

मुंबई में भारी बारिश...

स्कूलों में छुट्टियां घोषित

मुंबई : मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने बुधवार रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है. आईएमडी ने इससे पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन ताजा हालात के मद्देनजर इसे बदलकर 'रेड' कर दिया. मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद बीएमसी ने मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज को आज बंद रखने का आदेश दिया है.

नगर निगम आयुक्त और बीएमसी के प्रशासक इकबाल सिंह चहल ने बुधवार रात इस बारे में एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि 'मुंबई के लिए जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा का खयाल रखते हुए बीएमसी ने गुरुवार को शहर और उपनगरों के सभी नगरपालिका, सरकारी और निजी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों और सभी कॉलेजों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है.'

इससे पहले दोपहर में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें 26 और 27 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी. मुंबई में बुधवार को पूरे दिन लगातार भारी बारिश हुई, जिससे शहर की रफ्तार थम सी गई. सड़क पर गाड़ियों की बेहद कम आवाजाही दिखी, वहीं लोआज ट्रेन भी थोड़ी देरी से चलीं. बीएमसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, यहां मुंबई के फोर्ट, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, एलफिंस्टन रोड, ग्रांट रोड और अंधेरी, मरोल, जोगेश्वरी और गोरेगांव सहित उपनगरों सहित कई इलाकों में बुधवार रात 8 बजे समाप्त हुए 12 घंटों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई. वहीं इसी अवधि के दौरान द्वीप शहर, पूर्वी उपनगरों और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 92.82 मिमी, 80.13 मिमी और 94.13 मिमी की औसत वर्षा हुई.

धारा 353 (अ) के प्रावधानों में होगा फेरबदल

सरकारी बाबुओं से मारपीट करने पर सजा का है प्रावधान

मुंबई। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (अ) के प्रावधानों में किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने पर सजा का प्रावधान है। महायुति सरकार अब इस धारा में संशोधन करने जा रही है। उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लक्ष्यभेदी सूचना पर चर्चा के दौरान कहा कि धारा 353(अ) में संशोधन किया जाएगा।

फडणवीस ने विधायक सुभाष कांदे द्वारा सवाल पूछने पर कहा कि उन्हें भी धारा 353(अ) के दुरुपयोग की जानकारी मिल रही है। अगले 3 महीनों में इस धारा में संशोधन किया जाएगा। विधायक देवयानी फरांदे ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी इस धारा का इस्तेमाल कर जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें अब संशोधन की जरूरत है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में उन्होंने इस तरह का कानून बनाने को लेकर पहल की थी, क्योंकि उस वक्त सरकारी कर्मचारियों पर ज्यादा हमले हो रहे थे। अब ऐसी खबरें मिल रही हैं कि सरकारी कर्मचारी इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (अ) में कुछ संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि दोनों को न्याय मिल सके।

पुलिस निरीक्षक को जबरन छुट्टी पर भेजा गया...

शिंदे गुट के विधायक सुभाष कांदे ने नासिक के पुलिस निरीक्षक निलेश माईनकर पर जबरन उगाही का आरोप लगाया था। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की जांच सह आयुक्त स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दिए। इसके अलावा माईनकर को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। जिससे जांच में कोई व्यवधान न हो। कांदे ने इस पुलिस अधिकारी पर यह भी आरोप लगाया कि उसने जबरन उगाही कर करीब 5 से 10 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। जिसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते के जरिए की जा रही है।

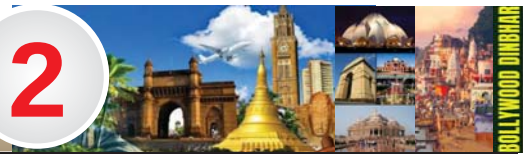

संपादकीय / लेख

लोकतंत्र पर हमला...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

इस्राइली संसद ने सोमवार को वह 'रीजनेबलनेस' बिल पास कर दिया, जिसे कथित न्यायिक सुधार का पहला चरण बताया जा रहा है। यह बिल नेतन्याहू सरकार की जुडिशरी को कमजोर करने की विस्तृत योजना का हिस्सा है और इसके खिलाफ वहां पिछले करीब छह महीने से व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद में बिल पास किए जाते समय विपक्ष मौजूद नहीं था, इसीलिए 64-0 से पास हो गया। लेकिन संसद के बाहर सड़कों पर उस समय भी हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि नेतन्याहू सरकार इस बिल को जुडिशरी पर हमला नहीं मानती। उसके मुताबिक, यह देश के अंदर सत्ता समीकरण को फिर से संतुलित करने की कोशिश है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि पावर इक्वेशन को रीबैलेंस करने के नाम पर सरकार ने जुडिशरी के अधिकार कम किए हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद न्यायपालिका को सरकार के फैसलों की समीक्षा करके उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं रह जाएगा। जाहिर तौर पर यह एक निर्वाचित सरकार द्वारा देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का ऐसा मामला है, जिसे दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों और समाजों के लिए चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। किसी जमाने में वामपंथी विचारधारा को लोकतंत्र के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में दक्षिणपंथ की तेजी से उभरती प्रवृत्तियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बनती दिख रही हैं। ऐसे में इसे हलके में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि इस्राइल के सबसे करीबी देशों में गिने जाने वाले अमेरिका ने भी उसे ऐसे विधेयकों पर जल्दबाजी न करने और आम सहमति बनाने का सुझाव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, नेतन्याहू को भेजे संदेश में यहां तक कह चुके हैं कि इन बिलों को पारित करने पर जोर देकर उनकी सरकार दोनों देशों के रिश्ते को दांव पर लगा रही है। लेकिन खुद भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू ने सभी सुझावों को दरकिनार करते हुए जुडिशरी के पर कतरने का अपना अजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पहले तो यह देखना होगा कि इस्राइल में इसके किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। इसे जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है वहीं इसके खिलाफ व्यापक हड़ताल की भी चेतावनी दी जा रही है। नेतन्याहू सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और वहां घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है दुनिया भर की लोकतांत्रिक शक्तियां इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लें। हालांकि यह ऐसी लड़ाई है, जिसे हर लोकतांत्रिक समाज को अपने स्तर पर और खुद लड़ना होगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की भी इतनी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि ऐसे मामलों में वह अपने नैतिक समर्थन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करे।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

दहिसर से मीरा-भाईंदर बस 10 मिनट में पहुंचे, एल एंड टी बनाने जा रही लिंक रोड,

वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 42 महीने में पूरा करना होगा प्रॉजेक्ट

- 1,959 करोड़ रुपये की लागत से होगा लिंक रोड का निर्माण
- दहिसर से मीरा-भाईंदर की दूरी महज 10 मिनट में होगी पूरी

मुंबईः दहिसर से मीरा-भाईंदर तक बनने वाली लिंक रोड को बनाने की जिम्मेदारी एल एंड टी कंपनी को मिली है। दहिसर से भाईंदर के बीच 5.3 किमी. लंबी लिंक रोड के बनाने पर बीएमसी 1,981 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस लिंक रोड के बनने के बाद दहिसर से मीरा-भाईंदर की दूरी महज 10 मिनट में पूरी की जा सकेगी। बीएमसी के उपायुक्त उल्हास महाले ने बताया कि 25 जुलाई को टेंडर फाइनल कर दिया गया है। तीन कंपनियों जे. कुमार, एल एंड टी एफकॉन्स ने टेंडर भरा था। एल एंड टी को छोड़ कर दोनों कंपनियों ने तय दर से प्लस में टेंडर भरा था, जबकि एल एंड टी ने -0.86 प्रतिशत में टेंडर भरा था। इसीलिए इस कंपनी को दहिसर-भाईंदर लिंक रोड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 42 महीने में कंपनी को यह प्रॉजेक्ट पूरा करना होगा। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू ने बताया प्रॉजेक्ट पूरा होने के बाद अगले तीन साल तक रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इस प्रॉजेक्ट के तहत दहिसर खाड़ी में लगभग 100 मीटर लंबा एक स्टील ब्रिज बनाया जाएगा। कुल 5.3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के लिए कुल 330 खंभे बनाए जाएंगे। पूरी सड़क सीमेंट कंक्रीट से बनेगी। बीएमसी को उम्मीद है कि प्रतिदिन 75 हजार वाहन इस लिंक रोड का उपयोग करेंगे। यहां आधुनिक तकनीक से लैश 7 मंजिला पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 550 गाड़ियों को पार्क किया जा सकेगा। साथ ही बस टर्मिनल और ट्रांसपोर्ट हब भी होगा, जो मेट्रो से कनेक्ट होगा।

यह होगी लिंक रोड की खासियत

बीएमसी ने दहिसर से भाईंदर के बीच 5.3 किमी लंबी कोस्टल रोड की योजना बनाई है, जो कि कांदरपाडा मेट्रो स्टेशन लिंक रोड दहिसर (प.) से शुरू होगी और सुभाषचंद्र बोस ग्राउंड भाईंदर (वेस्ट) तक जाएगी।

7 साल में तय हुआ कंपनी का नाम

दहिसर-भाईंदर के बीच प्रस्तावित इस लिंक रोड की परिकल्पना 2016 में सामने आई थी। लेकिन 7 साल बाद अब जाकर इसे बनाने वाली कंपनी का नाम फाइनल हुआ है।

ठाणे में स्वयंभू बाबा ने महिला के साथ किया बलात्कार! अब हुआ गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 60 वर्षीय स्वयंभू बाबा को एक महिला को बुरी आत्माओं और कष्टों से मुक्त कराने का लोभ दिखाकर उससे बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भायंदर थाने के अधिकारी ने कहा कि भायंदर क्षेत्र से 35 वर्षीय महिला ने स्वयंभू बाबा से संपर्क किया था, जिसने उसकी स्थिति का फायदा उठाकर उसकी मदद करने का आश्वासन देकर वर्ष 2016 से कई मौकों पर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया।

अधिकारी के मुताबिक, महिला को बाद में महसूस हुआ कि झूठे वादे करके उसे धोखा दिया जा रहा है और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी के अनुसार, शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं तथा काले जादू की रोकथाम एवं उन्मूलन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

कुत्तो के काटने से नहीं फैलेगी बीमारी मनपा कुत्तों का करेगी टीकाकरण

मुंबई : मनपा ने एनजीओ की मदद से हर साल लगभग एक लाख आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। मनपा का कहना है कि कुत्तों का टीकाकरण करने से कुत्तो के काटने से होने वाली बीमारी पर लगाम लगेगी।मनपा ने कुत्तो के टीकाकरण के लिए मिशन रेबीज और वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विसेज के साथ एक समझौता किया है। दोनों ही संस्था अपनी सेवाएं निःशुल्क देंगी । मनपा ने मुंबई में आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने और ' मुंबई को रेबीज मुक्त ' बनाने के लिए एक पहल की है ।मनपा ने इसके लिए रेबीज एंड वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विसेज (डब्ल्यूबी एस) के साथ समझौता किया है।जिसके तहत हर साल लगभग 1 लाख आवारा कुत्तों को रेबीज का टीका लगाया जाएगा। गौरतलब यह है कि दोनों संगठन इस पहल के लिए मुफ्त सेवाएं देंगी।आवारा कुत्तो के काटने से होने वाली रेबीज बीमारी फैलती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मनपा अब कुत्तों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। रेबीज वायरस स्तनधारियों संक्रमित करता है, अंततः रोग को मस्तिष्क तक फैलता है और मृत्यु का कारण बनता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक रेबीज के उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।जिसके आवारा कुत्तों का टीकाकरण करने के लिए एक मिशन शुरू किया है। अनुबंध के अनुसार, टीकाकरण कार्यक्रम सितंबर 2023 से शुरू होगा, जबकि जनवरी 2024 में कुत्तों की जनगणना की जाएगी। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, मिशन को फरवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाएगा।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट...

जिले के सभी स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पड़ोसी ठाणे और रायगढ़ समेत पूरे राज्य में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को मुंबई और ठाणे जिलेके लिए बारिश का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने रायगढ़ जिले के लिए बारिश का 'रेड' अलर्ट जारी किया है। इसके बाद रायगढ़ में जिला प्रशासन ने

26 जुलाई को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। इससे पहले मुंबई में अधिकतर जगहों पर मंगलवार सुबह बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश के बाद मुंबई में रविवार से बारिश की तीव्रता में कमी आई है। शहर के कई हिस्सों में सोमवार को बादल छंटने के बाद कुछ देर के लिए धूप भी खिली। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दो दिनों तक बाढ़ की चपेट में रहा। जिले के लोग अभी तक इससे उबर नहीं पाये हैं।

दो दिनों से बारिश थमी तो जिलेवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि, अब नागपुर क्षेत्रीय मौसम केंद्र की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार, चंद्रपुर जिले के लिए 25 से 29 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। पूवार्नुमान के अनुसार मौसम विभाग ने 26 से 27 जुलाई तक चंद्रपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चंद्रपुर जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 28 और 29 जुलाई की अवधि के दौरान चंद्रपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस अवधि के दौरान एक या दो स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है।

जब आसमान में तूफान, गरज और बिजली चमक रही हो तो क्या करें?

अगर बिजली गिरने के साथ बारिश का पूवार्नुमान हो तो बाहर जाने से बचें। यदि आप खुले क्षेत्र में हैं और आस-पास कोई आश्रय नहीं है, तो किसी निचले क्षेत्र में जाएं और अपने घुटनों पर सिर रखकर बैठें। यदि आकाश में बिजली चमकती है, तो घर के अंदर या किसी सुरक्षित इमारत में शरण लें। बालकनी, छत या घर के बाहर न रुकें। अगर आप घर पर हैं और घर में बिजली के उपकरण हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर दें। तार की बाड़, बिजली के खंभों और अन्य धातु की वस्तुओं से दूर रहें। अगर पानी में खड़े हैं तो तुरंत पानी से बाहर निकल जाएं।

मुंबई पुलिस को सुरक्षा निगम से 3000 कर्मी लेने के लिए मिली मंजूरी...

10 हजार पद पड़े हैं रिक्त

मुंबई : मुंबई पुलिस बल में सिपाहियों की कमी को दूर करने के मकसद से राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम से तीन हजार कर्मियों को लेने की मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के गृह मंत्रालय ने इस बाबत सोमवार को एक आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया कि मुंबई पुलिस बल दिन प्रति दिन के कार्य के लिए जनबल की कमी का सामना कर रहा है क्योंकि सिपाहियों के लिए स्वीकृत 40,626 पदों में से 10 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। जनवरी 2021 में राज्य सरकार के एक आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने सिपाहियों के 7,076 और चालक के 994 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।

मनपा ने अनधिकृत ढाबा... गैरेज और टपरी सहित

42 हजार 300 वर्ग फुट पर किया तोड़क कार्यवाइ

वसई : बारिश थमते ही वसई विरार शहर महानगरपालिका का जबरदस्त अनधिकृत निमार्णो पर तोडू कार्रवाई शुरू कर दी है,जिसमें ढाबा, टपरी, गैरेज व होल्डिंग्स आदि पर कार्रवाई की गयी है,इस तोडू कार्रवाई से अनधिकृत निर्माण करने वालो में दहशत व्याप्त है।बातदे कि,पिछले दिनों तेज बारिश से हाइवे रुक गयी थी। दरअसल,हाइवे पर बारिश का जलभराव अत्यधिक देखने को मिला है,जिससे भारी ट्राफिक देखने को मिला था। हाईवे पर जलभराव को लेकर आलाधिकारियों ने अनधिकृत निमार्णो संबंध को लेकर बताया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और तोडू मुहिम शुरू कर दी है। 25 जुलाई को वसई विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार व अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाल के मार्गदर्शन में उपायुक्त डॉ. किशोर गवस के नेतृत्व में प्र. सहायक आयुक्त (प्रभाग 'जी') मोहन संखे व कल्पेश कडव,गौरव पारिहार,(क. अभियंता.) व सुनील तेलगोटे (लिपिक) व मजदूर समेत एमएसएफ कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति में चिंचोटी नाका ते बापाणे फाटा परिसर क्षेत्र में 8 ढाबा,127 टपरी, 16 बांबू शेड,6 पत्रा शेड,13 होल्डिंग्स व 64 गैरेज पर जेसीबी लगाकर तोडू कार्रवाई की है। मनपा ने बताया कि कुलमिलाकर 42300 वर्ग.फुट में अनधिकृत निर्माण तोड़े गए है। ज्ञात हो कि,पिछले दिनों 42 ढाबा,32 टपरी,12 बांबू शेड,20 पत्रा शेड व 14 होर्डिंग्स पर तोडू कार्रवाई की थी।

कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर और अजित पवार के बीच हुई 'नोकझोंक'...

मुंबई: पिछले दो-तीन दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच धन आवंटन को लेकर जमकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी विपक्षी दल के नेताओं ने धन आवंटन को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोला था. इस बीच, इसे लेकर कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर और वित्त मंत्री अजित पवार के बीच विधानसभा हॉल में नोकझोंक हो गई. हॉल में यशोमती ठाकुर ने अजित पवार पर हमला बोला. यशोमती ठाकुर ने जवाब दिया, 'आप महाराष्ट्र को अपवित्र कर रहे हैं, यह तय है.'

गरमाया धन आवंटन का मुद्दा

यशोमती ठाकुर ने जताई आपत्ति

यशोमती ठाकुर की आपत्ति के बाद अजित पवार ने कहा, ''यशोमती, आप मेरी बहनों की तरह हैं. मेरी बात सुनो. तुम्हें मेरी बात सुनकर बोलने का अधिकार है. एक भाई के रूप में आपको शुभकामनाएं. चिंता मत करो.'' इस पर यशोमती ठाकुर ने कहा, ''15 दिन के अंदर ही आप सौतेले भाई जैसा व्यवहार करने लगे.'' इसके बाद अजित पवार ने कहा, ''आप अपना चश्मा बदल लें, मुझे सौतेले भाई की तरह मत देखें. मैं तुम्हें सौतेली बहन के रूप में नहीं देखता.

दी ये प्रतिक्रिया...

विधानसभा हॉल में अजित पवार से हुई तकरार के बाद यशोमती ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी. विधान भवन के बाहर 'टीवी9 मराठी' से बात करते हुए यशोमती ठाकुर ने अजित पवार को संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे लगा कि आप मेरे भाई हैं. लेकिन अब अगर भाई 15 दिन में ही सौतेला व्यवहार करने लगे तो कैसे काम चलेगा. यह महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता. आप महाराष्ट्र को अपवित्र कर रहे हैं, यह निश्चित है.''

दरअसल, विधानसभा में धन आवंटन को लेकर विपक्ष के आरोपों के बाद वित्त मंत्री अजित पवार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया. ''धन वितरित करते समय कोई भेदभाव नहीं किया गया. 2019, 2020 और 2021 के दौरान फंड आवंटन का सामान्य फॉर्मूला. हमने उसी फॉर्मूले को कायम रखने की कोशिश की है.

कोल्हापुर में दीवार गिरी... एक महिला की मौत, एक घायल

कोल्हापुर : कोल्हापुर के खासबाग मैदान में आज एक हादसा हो गया। दीवार गिरने से दो महिलाएं फंस गईं। इनमें से एक की मौत होने की खबर है। कोल्हापुर के केशवराव भोसले थिएटर में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में लोग आये थे। इसी दौरान खासबाग मैदान में बनी सुरक्षा दीवार ढह गयी। शुरूआत में बताया गया कि इस हादसे में दो महिलाएं शामिल थीं। महानगर पालिका के अधिकारी और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। अथक परिश्रम के बाद महिलाओं को बाहर निकाला गया। लेकिन उनमें से एक की मौत हो गई है। दूसरी महिला घायल है जिसका इलाज चल रहा है।

'अगर बीजेपी दोबारा आती है तो खत्म हो जाएगा...',

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है. उद्धव ठाकरे ने कहा, '2024 देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा. अगर यह (बीजेपी) सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो मुझे नहीं लगता कि यहां लोकतंत्र बचेगा'. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, यह आम लोग ही हैं जो लोकतंत्र को बचाएंगे. राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत के साथ दो-भाग के इंटरव्यू में, उन्होंने कई विषयों और महाराष्ट्र और भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बात की.

कब जारी होगा उद्धव ठाकरे का पूरा इंटरव्यू?

इंटरव्यू 26 और 27 जुलाई को शिवसेना (यूबीटी) के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा और मराठी अखबार, पार्टी के मुखपत्र सामना और इसके हिंदी टैब्लॉइड संस्करण दोपहर का सामना में दिखाई देगा.

एक सवाल पर ठाकरे ने कहा कि दिल्ली के सामने झुकना हमारी संस्कृति नहीं है. उन्होंने कहा, ''उद्धव ठाकरे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, उद्धव ठाकरे का मतलब बाला साहेब के विचार हैं.'' उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ''जिन्होंने बाबरी (मस्जिद विध्वंस) की जिम्मेदारी नहीं ली, वे राम मंदिर का श्रेय कैसे ले सकते हैं?''

संजय राउत ने लिया है ये इंटरव्यू

इंटरव्यू के एक प्रोमो में, जिसका शीर्षक है – 'आवाज महाराष्ट्राचा कुटुंबप्रमुखंचा' (महाराष्ट्र के परिवार के मुखिया की आवाज!) – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के बारे में बात की, जिसका नेतृत्व उन्होंने 28 नवंबर, 2019 से 30 जून, 2022 तक किया था. अपनी सरकार गिराने पर, ठाकरे ने कहा: '...सरकार बही नहीं थी...बांध केकड़े ने तोड़ दिया था''.

अंधेरी इलाके में भूस्खलन, खाली कराई गई आठ मंजिला एसआरए सोसायटी

मुंबई : अंधेरी इलाके में मंगलवार तड़के आठ मंजिला इमारत रामबाग, एसआरए सोसायटी की पहली और दूसरी मंजिल की खिड़की और दीवारों पर मलबा का कुछ हिस्सा गिरने से नुकसान हो गया है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भूस्खलन के बाद मनपा अधिकारियों ने इमारत से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मुंबई अग्निशमन विभाग ने जानकारी दी है कि रात करीब २ बजे मुंबई के अंधेरी ईस्ट चकाला इलाके में एक आवासीय सोसायटी के पास भूस्खलन की घटना घटित हुई है। मौके पर दमकल की चार गाड़ियां और मुंबई पुलिस के जवानों ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। मनपा के अधिकारियों ने आगे बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस नियंत्रण कक्ष ने सोमवार देर रात करीब दो बजे अंधेरी- पूर्व में महाकाली रोड पर स्थित रामबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पीछे भूस्खलन के बारे में मनपा को सूचित किया। मनपा के अधिकारियों के अनुसार, इमारत के पीछे स्थित पर्वतीय क्षेत्र से मिट्टी और चट्टानें गिरीं। उन्होंने बताया कि रामबाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में १६८ कमरे हैं और भूस्खलन को देखते हुए इमारत को एहतियातन खाली करा लिया गया है। अधिकारी के अनुसार, पुलिस कर्मी, वॉर्ड कर्मी और दमकल विभाग को मौके पर भेजा गया है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर दमकल की दो गाड़ियां भेजी हैं। मुंबई के मेघवाड़ी इलाके में स्थित पीपुल्स वेलफेयर इंग्लिश हाई स्कूल की लैब की गैलरी मंगलवार की सुबह गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। इसके अलावा अभी हाल ही में महाराष्ट्र के रायगड जिले के इर्शालवाड़ी में भी लैंडस्लाइड की घटना में ८७ लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे।

पत्रकारों के आर्थिक उत्थान के लिए जल्द ही हाईपावर कमेटी का गठन किया जाएगा - शंभुराजे देसाई

मुंबई : राज्य के ८५ प्रतिशत से अधिक पत्रकारों की आर्थिक स्थिति खराब है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए मंगलवार को विधान परिषद में मुद्दा उठा। धीरज लिंगडे सहित कई सदस्यों ने पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री शंभुराजे देसाई ने सदन के सदस्यों को आश्वस्त किया कि पत्रकारों के आर्थिक उत्थान के लिए जल्द ही हाईपावर कमेटी का गठन किया जाएगा। तो वहीं सेवानिवृत पत्रकारों को सरकार की ओर से दी जाने वाली निवृत वेतन की राशि बढ़ाकर २० हजार रुपए की जाएगी। देसाई ने कहा कि इसकी घोषणा अगले दो दिनों में की जाएगी।

सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत धीरज लिंगडे ने यह मुद्दा उपस्थित किया। इस पर सदस्य अभिजीत वंजारी, राजेश राठौड़, अशोक उर्फ भाई जगताप, डॉ. प्रज्ञा सातव आदि सदस्यों ने पत्रकारों की आर्थिक स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सदस्यों ने सदन में बताया कि राज्य में ८५ प्रतिशत पत्रकारों की आर्थिक स्थिति खराब है। उन्हें २० हजार रुपए से कम मासिक वेतन मिल रहा है। सरकार को इन पत्रकारों के आर्थिक उत्थान के लिए महामण्डल बनाने जरुरत है। सदस्यों ने कहा कि राज्य में ८५ प्रतिशत पत्रकारों की आय इतनी कम होती है कि उनके परिवार का गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से होता है। उनके आर्थिक विकास और उत्थान के लिए आर्थिक विकास संस्थान का गठन करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस मामले में उचित कदम उठाते हुए अण्णाभाऊ पाटील आर्थिक विकास मंडल बनाए। इस पर संबंधित विभाग के मंत्री शंभुराजे देसाई ने भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हाईपावर कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है।

निधि वितरण का फॉर्मूला आघाड़ी सरकार का: अजित पवार

मुंबई : विधानसभा में मंगलवार को 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की पूरक मांग को मंजूर कर लिया गया। विपक्षी दलों के विधायकों को फंड वितरण में भेदभाव के आरोप पर उपमुख्यमंत्री और वित्त और नियोजन मंत्री अजित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक जो फॉर्मूला था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अजित पवार के यह बात बोलते ही विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के सदस्य हंगामा मचाने लगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच अजित पवार को अपनी बात रखनी पड़ी। पिछले दो दिनों से विधायकों के फंड वितरण का मामला गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि फंड वितरण में उनके साथ भेदभाव हुआ है। विधानसभा में पूरक मांग पर हुई चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि विधायकों को जो निधि मिली है, उसके वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। निधि वितरण का सूत्र वर्ष 2020, 2021 और 2022 की तरह रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री के यह कहने पर विपक्षी सदस्य हंगामा मचाने लगे। अजित पवार ने कहा कि ग्रामीण और शहरों भागों का एकसमान विकास किया जाएगा। राज्य के विकास के लिए आय बढ़ाने के स्त्रोत पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निधि वितरण के मामले में नाना पटोले, यशोमति ठाकुर, वर्षा गायकवाड की अपनी राय हो सकती है, लेकिन किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मामले पर सकारात्मक मार्ग तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

विधानसभा में मंजूर 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की पूरक मांग में 13 हजार 91 करोड़ 21 लाख रुपए अनिवार्य खर्च, 25 हजार 611 करोड़ 38 लाख रुपए कार्यक्रम अंतर्गत और 2 हजार 540 करोड़ 62 लाख रुपए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत आर्थिक सहायता के तहत रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 41 हजार 243 करोड़ 21 लाख रुपए की सकल मांग दिख रही है, लेकिन वास्तवित भार 35 हजार 833 करोड़ 31 लाख रुपए है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि पार्टी के किसी भी विधायकों को पर्याप्त निधि नहीं मिली है। अजित पवार जब महाविकास आघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री थे तो शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों ने फंड नहीं मिलने का आरोप अजित पवार पर लगाया था, अब अजित पवार ने हमें (कांग्रेस) के विधायकों को फंड नहीं दिया है। शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि उनके विधायकों को भी मौजूदा राज्य सरकार ने फंड नहीं दिया है।

ठाणे में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई में 1 करोड़ के उपकरण किए गए नष्ट

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अवैध तरीके से रेत खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले एक करोड़ रुपये की कीमत के उपकरण नष्ट कर दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाणे के तहसीलदार युवराज बांगर ने बताया कि शिकायतों के बाद मंगलवार को मुंब्रा इलाके में छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान कई नाव समेत एक करोड़ रुपये के विभिन्न उपकरण नष्ट किए गए।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 27 जुलाई 2023

21 महीने से फरार चल रहेआरोपी को विरार आरपीएफ ने किया गिरफ्तार

वसई : अगर पुलिस चाह ले तो अपराधी कितना भी चालक हो वह एक न एक दिन पुलिस उसको पकड़ ही लेगी। ऐसा ही एक मामला विरार आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) ने सुलझाया है। विरार आरपीएफ ने 21 महिने बाद अपराध के मुख्य आरोपी को रे रोड से गिरफ्तार करने में सफल हुई है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के ऊपर लाखो रुपए रेल संपत्ति चोरी के मामले में विरार आरपीएफ में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था,जिनको न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है तथा 3 टैक्सियों को जप्त किया गया था,जबकि उक्त मामले का मुख्य आरोपी कुड्डूस इस्माइल शेख घटना के बाद से ही मुंबई से बांग्लादेश फरार हो गया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ 30 अक्टूबर 2021 को एनबीडब्ल्यू जारी किया था। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु विरार आरपीएफ निरीक्षक (विनीत कुमार) द्वारा आप्रवासन ब्यूरो, बांग्लादेश एंबेसी, से मुंबई के सभी पुलिस थानों एवं पासपोर्ट ऑफिस मुंबई इत्यादि सभी से लगातार संपर्क करके गिरफ्तारी करने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। विरार आरपीएफ निरीक्षक को मुखबिर से जानकारी मिली कि उक्त आरोपी बांग्लादेश से मुंबई में आ चुका है,सूचना मिलने के उपरांत आरपीएफ निरीक्षक विरार व टीम ने लगातार गोवंड शिवाजी नगर, मानखुर्द, कलवा, रे रोड भायखला व तुर्भे इत्यादि स्थानों पर लगातार निगरानी रखी, आरोपी के अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली उनपर भी निगरानी रखी,जिस-जिस एरिया में उक्त आरोपी गया उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज गाड़ियों के नंबर इत्यादि इकट्ठा करके उक्त आरोपी को दारुखाना झोपड़पट्टी संत सवता मार्ग रे रोड स्टेशन के सामने,मजगांव मुंबई इलाके से टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए आरपीएफ निरीक्षक विनीत कुमार की टीम ने पिछले 21 महीनो से लगातार प्रयत्न करती रही और आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी को रेलवे कोर्ट वसई रोड में हाजिर किया गया। जहाँ कोर्ट ने आरोपी को 5 दिनों के लिए आरपीएफ रिमांड में भेज दिया है। इस मामले में अबतक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले की जांच विरार आरपीएफ निरीक्षक कर रहे है।

1 जून 2023 से लेकर 23 जुलाई तक पालघर जिले में 13 नागरिकों की मौत

399 मकान हुए क्षतिग्रस्त,79 लोगों को वसई के आश्रय गृह में भेजा गया

जानलेवा होते गढ्ढे आये दिन बने रहे हादसों की वजह...

पालघर : इस साल मानसून की शुरूआत होने के बाद से अब तक पालघर जिले में 13 लोगों की मौत हुई है। ज्ञात हो कि, पालघर जिले में पिछले कुछ दिनों तेज बारिश के चलते सड़को से लेकर दुकान व घरों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वही बारिश में सड़को पर गढ्ढे ही गढ्ढे दिखाई दे रहे है। वसई विरार शहर की सड़को पर बड़े-छोटे गड्ढो का साम्राज्य स्थापित हो गया है। लोगो का रोड पर वाहन लेकर चलना भारी हो गया है, इन गड्ढो के कारण हर रोज छोटी-बड़ी दुर्घटनाये हो रही है। सड़को पर हुए गड्ढो को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठा रहे है। वही शिवसेना के (यूबीटी) उत्तर भारतीय वसई विरार तालुका प्रमुख सुरेंद्र सिंह का कहना है कि रोड पर पड़े खड्डे को जल्द से जल्द भरना चाहिए । मनपा के ठेकेदार द्वारा जल्द से जल्द रोड पर पड़े खड्डे को नही भरा गया तो शिवसेना बाध्य होकर मनपा के खिलाफ खड्डे भरो आंदोलन करने को मजबूर होगी।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई

मुंबई : नागालैंड में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उन अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं, जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण देने में विफल रहने पर सरकार से सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

ज्ञात हो कि कोर्ट ने इससे पहले महिलाओं के लिए ३३ फीसदी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अब याचिका में नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग को महिलाओं के लिए ३३ फीसदी आरक्षण को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा है। महिला आरक्षण उसी पर आधारित है। आप संवैधानिक प्रावधान से वैष्ठसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे यह समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया? जस्टिस कौल ने पूछा कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ कोई प्रावधान है? महिलाओं की भागीदारी का विरोध क्यों हो रहा है? जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं समान रूप से शामिल हैं।

नागालैंड के एटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसे महिला संगठन हैं, जो कहते हैं कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हमने आपको एक बहुत लंबी रस्सी दी है। आपने वचन दिया था कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन मुकर गए। यही हमारी चिंता है। यथास्थिति में बदलाव का हमेशा विरोध होता है। लेकिन किसी को यथास्थिति बदलने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जस्टिस कौल ने आगे कहा कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है। इसलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता।

गणेशोत्सव पर मंडप बनाने के लिए मनपा की 'एक खिड़की' योजना

मंडप अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन सुविधा, इस साल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस... फायर ब्रिगेड के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है

मुंबई : मनपा प्रशासन गणेशोत्सव के दौरान गणेशोत्सव मंडलों द्वारा तैयार किए जाने वाले मंडप बनाने के लिए अनुमति देने के लिए 'एक खिड़की' योजना उपलब्ध कराई है। गणेश मंडलो को ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा प्रदान की गई है। मंडलों को मंडप बनाने की अनुमति के लिए इस साल अधिक सुविधा उपलब्ध कराते हुए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मुंबई फायर ब्रिगेड के पास अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मनपा प्रशासन खुद ही अनुमति लेकर मंडल को मंजूरी दे देगी। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल के निर्देश पर मनपा प्रशासन ने गणेश मंडलो की इधर उधर की भागदौड़ से दूर रखते हुए मंडप बनाने के लिए अनुमति को लेकर एक खिड़की योजना उपलब्ध कराई है। मनपा की ओर से 1 अगस्त से 'वन विंडो' योजना शुरू की जाएगी। गणेश मंडलों को मंडप निर्माण की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी छूट दी गई है। मंडप बनाने वाले मंडल मनपा की वेबसाइट https://port□l.mcgm.gov.i□□f अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है । कम्प्यूटरीकृत सिंगल विंडो आवेदन सुविधा 1 अगस्त 2023 से उपलब्ध करायी जाएगी। गणेशोत्सव के साथ नवरात्रि मंडप के लिए भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

..पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास जाने की जरूरत नहीं

पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की अनुमति के लिए भी अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. मंडलों को उक्त मंडपों के लिए अनुमति शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मंडप परमिट निःशुल्क दिया जाएगा। एक हजार रुपये की सुरक्षा जमा राशि आवश्यक है जो त्यौहार खत्म होने के बाद लौटा दी जाएगी । गणेश मंडलों को आवेदन के साथ गारंटी पत्र भी देना होगा. इस उपक्रम का एक नमूना वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए और संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर के साथ आवेदन के साथ जमा करना होगा इस तरह की जानकारी मनपा उपायुक्त एवं गणेशोत्सव के

जोमैटो का डिलीवरी बॉय बना सरकारी अफसर, क्रेक किया पीसीएस एग्जाम

फूड डिलीवरी कंपनी जौमैटो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की कहानी

नई दिल्ली, एजेंसी। जोमैटो के डिलीवरी बॉय विग्नेश ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है। विग्नेश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपने ट्विटर हैंडल पर तमिलनाडु के विग्नेश की कहानी साझा की है। कंपनी ने बताया है कि कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाले शख्स ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा निकालकर अफसर रैंक की पोस्ट हासिल की है। जौमैटो ने उनकी कहानी शेयर करते हुए लिखा कि, 'विग्नेश के लिए एक लाइक जरूर करें, जिसने डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करते हुए हाल ही में तमिलनाडु लोक सेवा आयोग परीक्षा निकाली है।' सोशल मीडिया पर विग्नेश की पोस्ट वायरल हो रही है। विग्नेश की कहानी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया

यूजर्स उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दे रहे हैं।

जोमैटो ने दिल वाली इमोजी के साथ इसके कैप्शन में लिखा है कि विग्नेश के लिए एक लाइक करें, जिन्होंने जोमैटो डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करते हुए तमिलनाडु लोक सेवा आयोग परीक्षा पास की है। इस पोस्ट को अब तक 70 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस पोस्ट को तीन हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 50 से ज्यादा लोग इसपर कमेंट कर चुके हैं। इस पोस्ट पर लोग जमकर विग्नेश को बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि वाह विग्नेश बधाई हो। यूजर लिख रहे हैं कि मेहनत और लगन से हर चीज संभव है। विग्नेश के जज्बे को सलाम। वहीं कुछ यूजर्स मजाकिया अंदान में पूछ रहे हैं कि विग्नेश डिलीवरी बॉय का काम कब छोड़ रहे हैं।

12 को जारी हुआ रिजल्ट

बता दें कि तमिलनाडु लोक सेवा आयोग परीक्षा टीएनपीएससी की ओर से आयोजित एक राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा है। टीएनपीएससी ने 12 जुलाई को कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा ग्रुप 4 का रिजल्ट जारी किया था। यह परीक्षा ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, बिल कलेक्टर ग्रेड-1, बिल कलेक्टर, फील्ड सहायक और स्टोर कीपर जैसे कई पदों को भरने के लिए आयोजित की जारी है। टीएनपीएससी ग्रुप 4 के लिए लिखित परीक्षा 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी।

लैब ग्रोन डायमंड के आगे फीका पड़ा असली हीरा, 10 परसेंट तक गिर गया कारोबार

मुंबई एजेंसी। रियल डायमंड के कारोबार में तकरीबन 10 पर्सेंट की गिरावट देखी जा रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि अप्रैल के बाद एक्सपोर्ट में भी 10 पर्सेंट की गिरावट दर्ज हुई है। भारत डायमंड बोर्स के वाइस प्रेजिडेंट मेहुल भाई शाह का कहना है कि इसके पीछे अमेरिका, यूरोप और चीन में आर्थिक सुस्ती, रूस पर बैन से रफ डायमंड की सप्लाई में कमी आने से कारण अहम हैं। इसी के साथ लैब में तैयार किए जाने वाले डायमंड का बाजार जिस तेजी से उभरा है, इसका असर भी हुआ है। उदाहरण के लिए रियल डायमंड अगर पांच लाख रुपये का है, तो उसी के जैसा दिखने वाला लैब में तैयार डायमंड 20-40 हजार रुपये में मिल जाता है। यह बाजार नया है तो बढ़ रहा है। लैब ग्रोन डायमंड लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ये सिर्फ एक से चार सप्ताह में तैयार हो जाते हैं। ऐसे हीरों की बनावट, चमक, कलर, कटिंग, डिजाइन नैचुरल हीरे जैसी ही होती है और उसे भी सर्टिफिकेट के साथ बेचा जाता है।

शाह ने बताया कि रियल डायमंड की कीमतें भी थोड़ी नरम हुई हैं, लेकिन क्रिसमस तक बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, लक्ष्मी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल का मानना है कि ग्लोबली अब आज के दौर की पीढ़ी सगाई की अंगूठी के लिए असल डायमंड से दूर हो रहे हैं। लैब में तैयार हो रहे डायमंड का मार्केट 22 अरब डॉलर का है और इंडिया अपनी कारीगरी और वैल्यू एडिशन से इस बाजार पर अपना रुतबा जमा सकता है और यही हो भी रहा है। घरेलू खपत और ग्लोबल खपत में डबल डिजिट की ग्रोथ नजर आ रही है।

सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक सात लाख लोगों ने कराया पंजीकरण

नई दिल्ली, एजेंसी। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा अपनी राशि को वापस पाने के लिए अब तक सात लाख निवेशकों ने इस बारे में शुरू किए गए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि अब तक कुल 150 करोड़ रुपए की राशि के दावे प्राप्त हुए हैं। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में जमा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इस पोर्टल को कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को 'सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकार ने मार्च में कहा था कि चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा नौ माह में लौटा दिया जाएगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि अबतक सहारा के सात लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसके तहत कुल 150 करोड़ रुपए की राशि का दावा किया गया है।

कभी जूते की थी दुकान, फिर एयरलाइंस से कैसीनो तक का बना मालिक, गोपाल कांडा का ऐसा साम्राज्य

नई दिल्ली, एजेंसी। गीतिका सुसाइड केस के मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। एक दशक से भी पुराने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में राउज एवेन्यू की एक सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2012 के इस केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा आरोपी थे। एक समय जूते-चप्पल की दुकान चलाने वाले गोपाल कांडा ने अपना साम्राज्य तेजी से बढ़ाया। मौजूदा समय में उनके पास ऐसा किलानुमा महल है जिसकी कीमत 100 करोड़ के करीब बताई जाती है। आईए आपको बताते हैं कि आठवीं पास कांडा ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया। आज उनकी नेटवर्थ कितनी है।

जूते-चप्पल की दुकान

गोपाल ने अपने भाई गोविंद के साथ जूते और चप्पल की दुकान खोली थी। जब दुकान चल पड़ी तो उन्होंने बिजनस का दायरा बढ़ाया। जूते बनाने की फैक्ट्री

भी बाद में शुरू कर दी। जूते-चप्पल बेचते-बेचते गोपाल कांडा ने बिजनसमैन, बिल्डर और नेताओं से अपनी जान-पहचान बढ़ानी शुरू की।

साल 1998 में गोपाल कांडा ने गुरुग्राम में प्रॉपर्टी बिजनस में कदम रखा। इस समय यह बिजनस तेजी से बढ़ रहा था। कांडा ने छोटे-छोटे प्लॉट की खरीद-बिक्री शुरू की। इसके बाद वह हरियाणा के रियल एस्टेट के एक बड़े खिलाड़ी बन गए।

जब कांडा का साम्राज्य बढ़ने लगा तो उनके राज्य के कई प्रमुख राजनीतिज्ञों से संपर्क बन गए। कांडा के ऊपर गैंगस्टर से संपर्क होने का भी आरोप लगा। साल 2007 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कांडा की गतिविधियों की जांच कराने को कहा।

गोपाल कांडा ने साल 2009 में निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ा और जीता भी। गोपाल कांडा उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो लिए और उनको हुड्डा सरकार में गृह राज्यमंत्री बनाया गया। साल 2019 में जब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे हुई तो कांडा ने समर्थन का ऐलान कर दिया।

40 से ज्यादा कंपनियां

गोपाल गोयल कांडा ने 40 से ज्यादा कंपनियां बनाई। कांडा की ज्यादातर कंपनियों में उम्र और तजुर्बे से कम लोगों को बड़े पैकेज और बड़े ओहदे दिए गए। इनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। इन्हीं में से एक दिल्ली की गीतिका शर्मा थी।

अस्पताल से लेकर महल तक

कांडा ने सिरसा में एक बाबा ताराजी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके पास 13 एकड़ का विशाल परिसर है। इसमें 2.5 एकड़ में फैला स्कूल और उनका अपना महल है। इस ट्रस्ट के सालाना कार्यक्रम में बॉलीवुड के बड़े-बड़े गायक और फिल्म स्टॉर्स चीफ गेस्ट के रूप में लाए जाते थे।

करोड़ों की नेटवर्थ

गोपाल कांडा ने साल 2014 में चुनाव आयोग के समक्ष अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था। गोपाल कांडा के पास कुल चल संपत्ति 70 करोड़ 52 लाख 75 हजार 12 सौ रुपये हैं, जबकि अचल संपत्ति 14 करोड़ 93 लाख बताई थी। बताया था कि उनके पास 3923 ग्राम सोना है। साथ ही 72 कैरेट डायमंड हैं, जिनकी कीमत सात लाख 20 हजार रुपये है। उनकी पत्नी सरस्वती कांडा के पास करीब 10 करोड़ 85 लाख की चल संपत्ति है। वहीं 18 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति है। उनके पास 1562 ग्राम सोना है। 250 कैरेट डायमंड है जिनकी कीमत 25 लाख रुपये है।

जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओके के शरणार्थियों के लिए होंगी 3 सीटें

जम्मू-कश्मीर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में परिसीमन के बाद गणित बदलने वाला है। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक और तैयारी है, जिससे सीटों का गणित तो बदलेगा ही, विधानसभा भी बदली-बदली दिखेगी। दरअसल केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन ऐक्ट 2019 मे संशोधन की तैयारी कर रही है। इसे जल्दी ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में दो सीटें हिंसा का शिकार होकर पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए तय होंगी। इसके अलावा एक सीट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए होगी। इन तीनों ही सीटों के लिए कोई चुनाव नहीं होगा बल्कि तीनों सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इन तीनों सदस्यों को उपराज्यपाल की ओर से नामित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से राज्य में उपेक्षित और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी। उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन भी चल रहा है। इसके चलते 107 सीटों से बढ़ाकर विधानसभा में 114 सीटें करने का फैसला लिया गया है।

इन 114 सीटों में 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। अब तक कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के नाम पर कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन अब सरकार गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को इस कोटे के तहत विधानसभा भेजना चाहती है। गुज्जर बकरवाल खानाबदोश समुदाय है, जो अकसर सर्दियों के मौसम में जम्मू के आसपास रहता है, जबकि गर्मियां आते ही एक बार फिर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अपनी भेड़ों और अन्य पशुओं को लेकर निकल जाते हैं। फिलहाल नामित सदस्यों को लेकर जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक बहसबाजी जोरों पर है।

विधानसभा में नामित सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी

इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। अब तक दो महिला सदस्य ही मनोनीत की जाती थीं। भाजपा का कहना है कि यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है ताकि जनजाति समुदायों के राजनीतिक हितों का संरक्षण किया जा सके। फिलहाल कश्मीर में चर्चा इस बात को लेकर है कि मनोनीत सदस्यों को सदन में भेजने की प्रक्रिया क्या होगी।

पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों हो रही टेंशन

स्थानीय दलों का कहना है कि इसमें राज्य सरकार की सहमति जरूरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का कहना है कि मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने और आरक्षण के जरिए भाजपा चुनी हुई सरकार में दखल रखना चाहती है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में कश्मीर को कमजोर करना चाहती है।

झूठी पोस्ट करने पर माकपा नेता सुभाषिनी पर दर्ज हो एफआइआर : एनसीपीसीआर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) चाहता है कि मणिपुर में दो महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने के

मामले में एक 14 वर्षीय लड़के की आरोपित के रूप में गलत पहचान करने और उस पर संगीन आरोप लगाने के लिए माकपा नेता व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो।

सुभाषिणी अली ने किया था दावा: रविवार को सुभाषिणी ने प्रसारित वीडियो के स्क्रीनशाट के साथ आरएसएस की पोशाक पहने दो लोगों की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें दावा किया गया कि ये दोनों चार मई की उस घटना में शामिल थे, जिसमें भीड़ ने दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराई थी। एनसीपीसीआर ने मणिपुर पुलिस को एक नोटिस भेजकर कहा कि उसे माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली सहित तीन व्यक्तियों द्वारा नाबालिग लड़के की पहचान का राज खोलने से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें नाबालिग पर मणिपुर की हालिया घटना में अपराधी होने का आरोप लगाया गया है।

मामले की तत्काल जांच की जाए: इसके अलावा आयोग को यह भी बताया गया है कि नाबालिग की तस्वीरें प्रसारित करने से उसे मानसिक आघात पहुंचा है और वह सदमे की स्थिति में है। आयोग ने पुलिस से कहा कि उक्त अपराधियों के खिलाफ तुरंत एफआइआर दर्ज करने के लिए मामले की तत्काल जांच की जाए।

दिल्ली जल बोर्ड में करोड़ों रुपये की हेराफेरी, अब ईडी की छापेमारी से हड़कंप; मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। दिल्ली जल बोर्डबोर्ड में कथित तौर से गड़बड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह छापेमारी की गई है। अपनी जांच-पड़ताल के दौरान ईडी ने सोमवार को 10 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने कहा है कि जांच एजेंसी ने इस छापेमारी के दौरान कई कागजात भी जब्त किये हैं। दरअसल नवंबर 2022 में दिल्ली सरकार के एंटी-करप्शन ब्रांच ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर से हुए 20 करोड़ के घोटाले को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिन कंपनियों से बोर्ड ने टाई-अप किया था वो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी लोगों से बिल कलेक्शन कर रही थीं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट साल 2012 से 10 अक्टूबर 2019 तक का था।

प्रवर्तन निदेशालय इसी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और इसी जांच के तहत यह छापेमारी दिल्ली में हुई है।

एनसीआर को मिलेगी और रफ्तार, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच यहां बनेगी एक नई सड़क

नई दिल्ली, एजेंसी। एनसीआर में रहने वालों के लिए राहत की खबर है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एक नई सड़क बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। सेक्टर-146 के सामने हिंडन पुल से नोएडा को जोड़ने के लिए 850 मीटर की एप्रोच रोड बनेगी। यह 45 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। इसके दोनों ओर 7.5 मीटर चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार की जाएगी। इस सड़क को बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। दो-तीन महीने में सड़क बनाने का काम शुरू होने की उम्मीद है।

नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर जाम में आएगी कमी: यह सड़क ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक से सीधे जुड़ेगी। ग्रेटर नोएडा की तरफ से सड़क बनाने का काफी काम हो चुका है। इससे नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर जाम में कमी आएगी। सड़क बनाने के लिए जारी किए गए टेंडर में सड़क निर्माण पर करीब 43.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि तय समय बाद टेंडर प्रक्रिया में आने वाली कंपनियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की

जाएगी। यहां पर कई साल से जमीन का विवाद बना हुआ था। इससे वर्ष 2019 से काम बंद पड़ा था। इसके साथ ही एप्रोच रोड का काम भी नहीं शुरू हो पाया था। अब यहां जमीन का विवाद सुलझाने के अलावा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में मुआवजा दर भी बढ़ा दी हैं। किसान यहां पर डूब क्षेत्र की दरों पर मुआवजे के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए प्राधिकरण ने सड़क बनाने के लिए जमीन लेने को नई दरों की मंजूरी 23 अप्रैल 2023 को बोर्ड से ली थी। डूब क्षेत्र जमीन की दरें 2014 में 3500 रुपये वर्ग मीटर निर्धारित थीं। नई दरें सेक्टर के हिसाब से 5326 रुपये की गई हैं। इन दरों पर 4 हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण करीब 25 किसानों की जमीन लेगा। अधिकारियों का दावा है कि किसान इस पर तैयार हो गए हैं। मौके पर काम शुरू करने की सहमति दे दी है, इसलिए यहां पर काम शुरू करवाए जाने की तैयारी कर ली गई है।

साल में दो फिल्में करेंगी सोनम

मां बनने के बाद अपने बच्चे को समय देने के लिए अभिनेत्रियों को अपने काम को मैनेज करना पड़ता है। नीरजा फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर भी अब कुछ ऐसा ही करने वाली हैं। साल 2022 में मां बनीं सोनम अब फिल्मों में वापसी की तैयारी में हैं।

लेकिन इससे पहले उन्होंने खुद के लिए कुछ नियम बना लिए हैं। इन नियमों के तहत सोनम साल में केवल दो प्रोजेक्ट्स ही करेंगी। इस बारे में और जानकारी देते हुए सोनम कहती हैं कि मुझे हमेशा उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना पसंद रहा है, जिन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया हो। मैं अब साल में दो प्रोजेक्ट्स ही करना चाहती हूं। मुझे ऐसी कहानी की तलाश है, जो मनोरंजक हो। मैं उन विषयों की ओर आकर्षित हो रही हूं, जो ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करे, ताकि हम एक परिवार, एक समुदाय के रूप में फिल्मों को साथ बैठकर देख पाएं।

मैं उन विषयों की ओर आकर्षित हो रही हूं, जो ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करे, ताकि हम एक परिवार, एक समुदाय के रूप में फिल्मों को साथ बैठकर देख पाएं।

मुझे आज भी याद है कि मैं एक्टर क्यों बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी, मुझे ऐसी फिल्में पसंद थीं, जिन्हें मैं अपने पूरे परिवार के साथ देख सकूं। अपने परिवार के साथ फिल्में देखते हुए मैं कई तरह की भावनाओं से गुजरी हूं। वे पल आज भी मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत यादें में से एक हैं। उसी तरह के सिनेमा का हिस्सा आज भी बनना चाहती हूं। मेरे लिए कमर्शियल और परिवार का मनोरंजन करने वाली फिल्में हमेशा से प्राथमिकता रही हैं। मैं इसी तरह की फिल्मों से वापसी करना चाहती हूं। सोनम अपने लिए वह दो प्रोजेक्ट्स चुन चुकी हैं, जिसकी शूटिंग वह अगले साल शुरू करेंगी।

'सत्यप्रेम की कथा' का दुनियाभर में बजा डंका, 125 करोड़ के पार हुई कार्तिक-कियारा की फिल्म

कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' को देश ही नहीं दुनिया भर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. बॉक्स ऑफिस नंबर इसका सबूत हैं. इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को सभी एज ग्रुप के लोगों ने पसंद किया. इसी के साथ इस फिल्म ने अच्छी-खासी कमाई भी कर ली है. चलिए यहां जानते हैं सत्यप्रेम की कथा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो गया है. ऑडियंस के प्यार और 'सत्यप्रेम की कथा' को मिले जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ फिल्म ने अब दुनिया भर में लगभग 125 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ ही यह फिल्म साल की सरप्राइजिंग हिट बनकर उभरी है. इसमें कोई दो राय नही है कि सत्यप्रेम की कथा ने खुद को एक कंपलीट फैमिली एंटरटेनर फिल्म के रूप में साबित किया है, जिसे परिवार के साथ-साथ युवा दर्शकों का भी प्यार मिला है. फिल्म के मंत्रमुग्ध कर देने वाले सीन्स से भरपूर एक प्योर लव स्टोरी, कार्तिक और कियारा की

ब्लॉकबस्टर जोड़ी, अमेजिंग सॉन्स इस फिल्म की यूएसपी है. ये फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में जमी हुई है. 'सत्यप्रेम की कथा' का ओपनिंग वीकेंड काफी शानदार रहा था. इसके बाद फिल्म की कमाई में उतार-चढ़ाव देखा गया था. हालांकि लगातार घटती कमाई के बावजूद 'सत्यप्रेम की कथा' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. रिलीज के 27 वें दिन यानी चौथे मंगलवार को फिल्म ने 30 लाख का बिजनेस किया. जिसके बाद इसकी कुल कमाई 82.56 करोड़ रुपये हो गई है. बता दें कि 'भूल भुलैया 2' के बाद कियारा और कार्तिक की सुपरहिट जोड़ी 'सत्यप्रेम की कथा' में दूसरी बार नजर आई है. इस फिल्म में कियारा और कार्तिक के अलावा सुप्रिया पाठक कपूर, गजराज राव, सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल, राजपाल यादव, निर्मित सावंत और शिखा तलसानिया ने भी अहम रोल प्ले किया है. फिल्म का निर्माण नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और नमः पिक्चर्स द्वारा जॉइंटली किया गया है.

रणवीर ने उड़ाया आलिया का मजाक

करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों फिल्म का प्रमोशन जोर-शोर से चल रहा है। लीड स्टार्स रणवीर सिंह और आलिया भट्ट कई शहरों में जाकर प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए कोलकाता पहुंचे। पश्चिम बंगाल की राजधानी में रणवीर और आलिया की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए एक प्रमोशनल इवेंट ऑर्गनाइज किया गया था। इस इवेंट में दर्शकों का दिल जीतने के लिए आलिया भट्ट ने कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने इवेंट में अपने फैंस को लुभाने के लिए बंगाली भाषा सीखी थी, लेकिन स्टेज पर जाते ही आलिया अपनी सारी लाइन ही भूल गईं। एक्ट्रेस ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

क्लिप में देखा जा सकता है कि इवेंट से पहले आलिया भट्ट बंगाली भाषा में अपनी लाइन याद करने की कोशिश कर रही हैं। वह आखिरी मोमेंट तक बड़ी मुश्किल से अपनी लाइन याद करती नजर आईं, लेकिन स्टेज पर जाते ही वह कन्फ्यूज हो गईं। 'नमस्कार कोलकाता' के बाद आलिया को अपनी लाइन याद नहीं आ रही थी।

जब आलिया लाइन भूलती हैं, तब रणवीर सिंह उनके मजे लेते हुए कहते हैं, ₹सो क्यूट यार। तू पूरी प्रिपरेशन करके आई थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पर भूल गई।₹ आलिया उनका चेहरा देखने लगती हैं तो रणवीर कहते हैं कि वह उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जीके नहीं आती है। हालांकि, बाद में आलिया भट्ट अपनी पूरी लाइन अच्छे से बोल देती हैं और ऑडियंस खुश हो जाती है। रणवीर भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। आलिया सफाई देते हुए कहती हैं, ₹मैं कल सुबह से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जब यहां आई और आप लोगों का चेहरा व लाल रंग देखा तो सब भूल गई, लेकिन मैं बस आपको लोगों का अभिवादन करना चाहती थी।₹ रणवीर ने कहा कि उन्होंने इस जेस्चर से उनका दिल जीत लिया है।

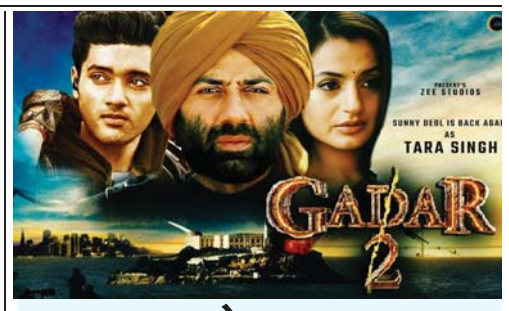

KRK ने 'गदर 2' को बताया वाहियात

सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब ये इंतजार कुछ ही समय में खत्म होने जा रहा है। गदर के पहले पार्ट को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और दूसरा भी उन्होंने ही किया है। गदर 2 का टीम अबतक जिस तरह से प्रमोशन कर रही वह उनके फेवर में ही जा रहा है। हालांकि फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक फिल्म को लेकर एक दावा किया है। उन्होंने गदर 2 को बहुत ही बेकार बताया है।

केआरके के ट्वीट के बाद से ये फिल्म फिर सुर्खियों में आ गई है। केआरके ने फिल्म को वाहियात बताया है। केआरके ने ट्वीट किया- किसी ने गदर 2 देखी है और उनके मुताबिक गदर 2 साल की सबसे वाहियात फिल्म है। अनिल शर्मा का डायरेक्शन 80 के दशक की तरह। कहानी और स्क्रीनप्ले बहुत कमजोर है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 3 दिन भी टिक नहीं पाएगी।

केआरके अपने ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। उनके ट्वीट अक्सर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। उन्होंने अब जो गदर 2 के लिए कहा है उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'ये बज सिर्फ प्रेंचाइजी की वजह से है जो लोगों को सिर्फ शुरू के तीन दिन ही खींच पाएगा। ये फिल्म के लिए खतरनाकर हो सकता है क्योंकि ये गदर की लेगेसी को आगे नहीं ले जा पाएंगी।' वहीं दूसरे ने लिखा- 'चल हवा आने दे।'

गर्व महसूस करते हैं जामवाल

बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्टों में शामिल होने पर गर्व महसूस करते हैं। विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जहां उनका नाम गुगल सर्च इंजन पर दुनिया के टॉप मार्शल आर्टिस्टों में जैकी चैन, जेट ली, ब्रूस ली, जॉनी ट्राई गुयेन, स्टीवन सीगल, डॉनी येन और टोनी जा जैसे जाने-माने मार्शल आर्टिस्टों के साथ दिखाई दे रहा है। विद्युत जामवाल ने बताया, मेरे लिए यह हमेशा पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की स्वीकृति है, जो सभी मार्शल आर्ट की जननी है। मुझे सभी मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की जननी का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व महसूस होता है। यह एक पूर्ण सम्मान है।

'ड्रीम गर्ल 2' का पहला लुक रिलीज

बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पहला लुक रिलीज हो गया है। आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल के सीक्वल ड्रीम गर्ल 2 में काम कर रहे हैं। ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे की भी अहम भूमिका है। फिल्म ड्रीमगर्ल 2 का पहला लुक रिलीज हो गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना दो रूपों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ वह पूजा और दूसरी तरफ करम के रूप में नजर आ रहे हैं। पूजा के रूप में वह ब्लाउज और स्कर्ट पहने नजर आ रहे हैं। उसके लंबे बाल हैं और वह लिपस्टिक लगाते हुए शीशे में देख रहा है। वहीं शीशे के दूसरी तरफ करम बने आयुष्मान गुलाबी टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं। ड्रीम गर्ल 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'यह तो सिर्फ पहली झलक है। शीशे में दिखने वाली चीजें कहीं खूबसूरत हैं और यह तो सिर्फ पहली झलक है। ड्रीम गर्ल 2 एकता आर कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित और राज शांडिल्य द्वारा निर्देशित हैं। यह फिल्म 25 अगस्त 2023 को रिलीज होने जा रही है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com .